दै. देशबंधु, भोपाल

28 OCT 2010

मंत्रियों को नसीहत

मध्यप्रदेश इन दिनों

भारत शर्मा

प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठकों में और कुछ हो न हो, मंत्रियों की लानत-मलामत जरुरी होती है। रतलाम में हुई पिछली बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने मंत्रियों को शराबी और अय्याश कह दिया था, तो इस बार होशंगाबाद में हुई बैठक में प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने मंत्रियों पर आरोप लगा दिया, कि वे छह-छह माह तक जिलों में नहीं जाते। श्री झा की इस टिप्पणी से मंत्री खासे नाराज़ हैं। कई तो खुलकर सामने भी आ गए। उनका कहना है, कि मंत्रियों के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुले रहते हैं, वहीं कुछ कहते हैं, कि अगर मंत्री काम नहीं करते, तो सरकार के सार्थक परिणाम कहां से आते? हालांकि वरिष्ठ मंत्री बाबूलाल गौर ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया, कि कार्यकर्ताओं के कहने पर एस पी व कलेक्टर के स्थानांतरण नहीं किए जा सकते। श्री गौर की यह टिप्पणी गौर करने लायक है, इससे साफ होता है, कि भाजपा कार्यकर्ता मंत्रियों व सरकार पर किस हद तक दबाव बनाते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है, कि इस हाल में जिला प्रशासन कितनी स्वतंत्रता के साथ काम कर पाता होगा। मजेदार बात यह है, कि श्री गौर कार्यकर्ताओं पर स्थानांतरण के लिए दबाव बनाने की बात कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से कह रहे थे, कि वे स्थानांतरण के लिए दबाव न बनाया करें। जाहिर है, कि नीचे से ऊपर तक एक ही काम चल रहा है।

शिवराज के गुणगान

किसी हिन्दी फिल्म का एक गाना है- मेरे प्यार की उमर हो इतनी सनम, तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खतम। भाजपा कार्य समिति की बैठकें भी कुछ इसी तर्ज पर हो रही हैं। इनमें केवल मंत्रियों के खिलाफ टिप्पणी ही नहीं की जाती, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गुणगान भी हर बार किया जाता है। अमूमन हर बैठक में पारित होने वाला राजनैतिक प्रस्ताव एक सा ही होता है। जिसकी शुरुआत प्रदेश में अच्छा काम करने के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ से होती है और अंत केन्द्र सरकार की नीतियों व प्रदेश सरकार के साथ किए जा रहे भेदभाव के विरोध के साथ। इस बैठक में भी केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही गई। वहीं सदस्यता बढ़ाने के लिए उन लोगों को सदस्य बनाने को कहा गया, जिन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल चुका है या मिल रहा है। बैठक में यह भी तय किया गया, कि ऐसे हितग्राहियों के सुझावों के आधार पर योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। बैठक में कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से सर्वोपरि बताया गया और संगठन को मजबूत करने की बात की गई। हालांकि संगठन कितना मजबूत है, इसका खुलासा भी प्रभात झा ने किया। उनका कहना था, कि भाजपा के एक जिले के जनप्रतिनिधि दूसरे जिले के जनप्रतिनिधियों को नहीं पहचानते।

बड़े चेहरे नदारद

भाजपा कार्यसमिति की बैठक से इस बार कई बड़े चेहरे नदारद रहे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार के अलावा नरेन्द्र सिंह तोमर, थावरचंद गेहलोत, कैलाश जोशी, सुषमा स्वराज व सुमित्रा महाजन भी इस बैठक में नहीं थीं। कारण बिहार चुनाव को बताया गया। वहीं कई मंत्री भी इस बैठक में नहीं थे, जो गए उनमें से भी कई उद्घाटन सत्र के बाद वापस लौट गए। बैठक में एक पूर्व मंत्री कमल पटेल तो पहुंचे, जो हत्या के साक्ष्य छुपाने के आरोप में जेल काटकर वापस आए हैं, पर हत्या के मामले में घिरे दूसरे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा इस बैठक से दूर रहे।

ढाई लाख करोड़ के करार

खजुराहो में हुए निवेशक सम्मेलन में दो दिन में करीब ढाई लाख करोड़ के करारों पर हस्ताक्षर किए गए। माना जा सकता है, कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार की जा रही कोशिशों से अब निवेशक प्रदेश की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। इस बार निवेशक सम्मेलन में पहली बार विदेशी निवेशकों की भी भागीदारी रही। इस सम्मेलन में पहले दिन जहां शामिल हुए वहीं दूसरे दिन अनिल अंबानी। इसलिये दोनों ही दिन सम्मेलन की रौनक बनी रही। इस दौरान कुल 107 करारों पर हस्ताक्षर किए हुए इनमें से अकेले अंबानी समूह 75 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हालांकि इस बार सरकार ने अपनी उद्योग नीति में कुछ संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है, कि जो स्थानीय लोगों को रोजगार देगा, उसे अधिक सुविधाएं दी जाएंगीं। साथ ही यह भी साफ किया है, कि अगर समय पर काम नहीं किया, तो करार को रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार हर तीन माह में करारों की समीक्षा करेगी। सरकार ने ये शर्तें पुराने अनुभवों को देखते हुए रखी हैं। पिछले निवेशक सम्मेलनों में जितने करार किए गए थे, उनमें से 5 फीसदी भी धरातल पर नहीं उतरे, जिस कारण सरकार को कुछ करार रद्द भी करना पड़े।

संसाधनों पर नजर

खजुराहो में हुए निवेशक सम्मेलन का यदि विश्लेषण किया जाये, तो एक बात साफ हो जाती है, कि अधिकांश उद्योगपतियों की नजर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर है। इससे पहले के सम्मेलनों में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिली थी। प्रदेश में पहले भी सर्वाधिक निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ था। सरकार ने तमाम ऐसे पूंजीपतियों को जमीनें और खदानें भी दे दी थी, पर उनमें से कई ने अभी तक काम ही शुरु नहीं किया है। वहीं कंपनियों की मनमानी के खिलाफ प्रदेश के कई हिस्सों के निवासियों में असंतोष भी पनप रहा है। इस बार भी जो करार हुए हैं, उनमें से भी अधिकांश सीमेंट व ऊर्जा से ही जुड़े हैं। इस बार पूंजीपतियों की नजर प्रदेश के बॉक्साईट भंडार पर भी पड़ी है। कहा जा सकता है, इस सम्मेलन के बाद प्रदेश में संसाधनों का दोहन और बढ़ेगा और स्थानीय लोगों का असंतोष भी बढ़ेगा।

सम्मेलन में राजनीति

केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंध एक दूसरे के सहयोगी के होते थे, पर अब इनमें तल्खी आती जा रही है। प्रदेश सरकार ने निवेशक सम्मेलन के लिए केन्द्र सरकार के मंत्रियों को आमंत्रित किया था, तो प्रदेश से मंत्री बने 4 नेताओं ने आने की सहमति दी थी, पर आए केवल एक केन्द्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अरुण यादव। उन्होंने सम्मेलन में ही प्रदेश में लगने वाले करों पर सरकार की खिंचाई कर दी। उनका कहना था, कि यहां कर अधिक हैं, इसलिए यहां पहले से स्थापित उद्योग भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इसके जबाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी राज्य के खराब राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए के लिए केन्द्र को दोषी करार दिया। आरोप-प्रत्यारोप की इस राजनीति को किसी भी नज़र से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार के जितने भी सम्मेलन राज्य सरकारें आयोजित करती हैं, वे केन्द्र सरकार द्वारा बनाई नीति के अनुसार ही हो रहे है, फिर केन्द्र सरकार का मंत्री ही निवेशक सम्मेलन में निंदा करे,यह बात समझ में कम ही आती है। श्री यादव मध्यप्रदेश के हैं और वे यहां आते भी रहते हैं। यह बात वे किसी और समय, किसी और मंच पर भी उठा सकते थे।

और अंत में

प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव काफी जानकार माने जाते हैं। पर कई बार अधिक ज्ञान दूसरों की परेशानी का कारण बन जाता है। पिछले दिनों राजधानी में पानी संरक्षण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ जिला प्रशासन ने करार किया। कार्यक्रम राजधानी भोपाल में हुआ। समारोह में बोलते हुए श्री भार्गव ने टाटा व बिरला जैसी कंपनियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा, कि इन उद्योगपतियों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए कभी भी शराब या सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं किया। श्री भार्गव जब यह बात कर रहे थे, तो उसको सबसे ज्यादा असर आईटीसी कंपनी के प्रतिनिधियों पर पड़ा, जिन्होंने दो जिलों के साथ करार किया है। बता दें, कि आईटीसी देश की सिगरेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है।